



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2000/श्रावण 17, 1922

No. 178]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2000/SRAVANA 17, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2000

अंतिम जांच-परिणाम

विषय: रूस और यूरोपीय संघ (ई.यू) से विटामिन सी के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच
अंतिम जांच परिणाम

26/1/99-डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा उसके सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए,

क. कार्य पद्धति

निम्नलिखित कार्य पद्धति अपनाई गई है -

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 17.1.2000 की अधिसूचना द्वारा रूस और यूरोपीय संघ (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश भी कहा गया है) से विटामिन सी (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में

पाटनरोधी जांच के बारे में प्रारंभिक निष्कर्षों को अधिसूचित किया था तथा हितबद्ध पार्टियों से इसके प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचार भिजवाने का अनुरोध किया था ।

- (ii) प्राधिकारी ने ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति भेजी थी जिनसे पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर प्रारंभिक निष्कर्षों के बारे में अपने विचार, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था;
- (iii) प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति नई दिल्ली स्थित रूस के दूतावास तथा यूरोपीय संघ के शिष्ट मंडल को भी इस अनुरोध के साथ भेजी थी कि निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों को प्रारंभिक निष्कर्षों पर अपने-अपने विचार उपर्युक्त पैरा(i) और (ii) में यथानिर्धारित समय सीमा के भीतर भेजने की सलाह दी जाए;
- (iv) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पार्टियों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया । मौखिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने वाली सभी पार्टियों से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था उक्त पार्टियों को सलाह दी गई थी कि प्रतिपक्षी पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां प्राप्त कर लें और उनका खंडन यदि कोई हो, प्रस्तुत करें । इस प्रकार हितबद्ध पक्षों से प्राप्त लिखित अनुरोधों पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस जांच परिणामों में विचार किया है ।
- (v) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पार्टियों को विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों वाली सार्वजनिक फाइल उनके अनुरोध पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाई थी;
- (vi) प्रारंभिक निष्कर्षों की घोषणा से पहले हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए जिन तर्कों को अधिसूचित किए गए प्रारंभिक निष्कर्षों में प्रकाशित किया गया है, उन्हें संक्षिप्तता के कारण इसमें दोहराया नहीं गया है । परन्तु प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों पर, इन निष्कर्षों में उचित ढंग से विचार किया गया है ।
- (vii) प्राधिकारी द्वारा जहां तक संभव था, निर्यातकों द्वारा दिए गए आंकड़ों की जांच की गई । निदेशालय के अधिकारियों के एक दल ने निर्यातकों के परिसरों अर्थात् मै0 बी ए एस एफ प्लांट एवं कारपोरेट आफिस क्रमशः डेनमार्क तथा जर्मनी में जांच की ।
- (viii) उपरोक्त नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए विचार किए गए अनिवार्य तथ्यों/आधार का खुलासा ज्ञात हितबद्ध पार्टियों के लिए दिनांक 21.7.2000 को किया गया था और उन पर मिली टिप्पणियों पर भी इन निष्कर्षों में विधिवत विचार किया गया है ।
- (ix) इस अधिसूचना में xxx किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने नियमों के अधीन उसे गोपनीय ही माना है ।

ख. याचिकाकर्ताओं, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार और प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच

याचिकाकर्ता, निर्यातकों तथा आयातकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और उन्हें संक्षेप में नीचे दिया गया है जो समान स्वरूप के हैं, उन्हें सक्षिप्तता की दृष्टि से दोहराया नहीं गया है।

(i) याचिकाकर्ता के विचार

- (1) माननीय सिगार के हाल के निर्णय के अनुसार अनेक अपीलों में शुल्क में यू एस डालर के रूप में संशोधन किया गया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भी हाल ही में जारी की गई कुछेक सिफारिशों में यू एस डालर के रूप में ही शुल्कों की सिफारिश की है। अतः अनुरोध है कि अंतिम निर्धारण के समय यू एस डालर के रूप में शुल्कों की सिफारिश की जाए।
- (2) यद्यपि संबद्ध देशों में अनेक निर्यातक हैं, लेकिन केवल दो निर्यातकों ने ही उत्तर दिया निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्राप्त इस सीमित प्रतिक्रिया से भी सुनवाई के दौरान यह पाया गया है कि एक निर्यातक मै0 मेर्क ने मौखिक सुनवाई में भाग नहीं लिया जिससे रूचि तथा सहयोग के अभाव का पता चलता है। अनुरोध है कि मै0 मेर्क को लिखित रूप में अनुरोध प्रस्तुत करने की अनुमति न दी जाए क्योंकि लिखित में अनुरोध करने की अनुमति केवल उन हितबद्ध पार्टियों के लिए है जो सुनवाई के दौरान उपस्थित थे और जिन्होंने विचार व्यक्त किए थे।
- (3) मै0 बी ए एस एफ ने घरेलू बाजार में बिक्रियों तथा उत्पादन की लागत से संबंधित ब्यौरे दिए हैं। कंपनी द्वारा दी गई सूचना से दिखाई देता है कि कंपनी ने घरेलू बाजार में घाटे पर विटामिन-सी की बिक्री की। वास्तव में, मौखिक सुनवाई के दौरान भी निर्यातक के प्रतिनिधि ने स्पष्ट रूप से माना था कि विटामिन-सी की बिक्रियों पर उन्हें हानि उठानी पड़ रही है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में कंपनी के उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।
- (4) कंपनी द्वारा गैर-गोपनीय अनुरोध, विशेष रूप से उत्पादन की लागत का विश्लेषण करने के बाद हमने पाया कि मै0 बी ए एस एफ ने अनेक लागत मदों के लिए बहुत ही कम प्रति इकाई लागत का दावा किया है। जिनमें महत्वपूर्ण हैं—परिवर्तनीय उत्पादन लागत, प्रशासनिक लागत तथा ब्याज लागत। यह स्मरणीय होगा कि कंपनी के प्रतिनिधि ने मौखिक सुनवाई के दौरान आर एंड डी पर बहुत जोर दिया था। हम भी जानते हैं कि बी ए एस एफ आर-एंड डी पर भारी खर्च करती है। तथापि कंपनी ने दावा की गई उत्पादन लागत में इसके लिए व्यय की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है।
- (5) उपर्युक्त को तथा कंपनी द्वारा दर्ज की गई सूचना के गोपनीय स्वरूप को देखते हुए यह अनुरोध है कि अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करने से पूर्व कंपनी द्वारा दायर की गई सूचना की विस्तृत जांच की जानी चाहिए। निर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्यातक के विभिन्न दावों का अंतिम निर्धारण हेतु स्वीकार करने से पूर्व उनका सत्यापन करना चाहिए।

- (6) मै0 मेर्क के जी एए ने घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों के न तो कारोबार के अलग अलग ब्यौरे दिए और न ही उत्पादन लागत के ब्यौरे ही दिए । कंपनी द्वारा दायर की गई सूचना कंपनी के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त नहीं है । अनुरोध है कि कंपनी को असहयोगी माना जाना चाहिए और निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया सामान्य मूल्य का मूल्य निर्धारण करने के प्रयोजन से विटामिन सी के उत्पादन के लिए खर्च की गई लागतों के बारे में हमारे द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मेर्क के उत्पादन की लागत निकाली जाए ।
- (7) मै0 बी ए एस एफ ने भारत को अपने निर्यातों के बारे में ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं । कंपनी ने अंतर्देशीय भाड़े, समुद्री भाड़े तथा पैकिंग के कारण निर्यात कीमत से समायोजनों का दावा किया है । तथापि बीमा और पत्तन व्यय के लिए किसी भी समायोजन को प्रकट नहीं किया है । अनुरोध है कि इन खर्चों के लिए निर्यात कीमत को समायोजित किया जाए ।
- (8) मै0 मेर्क के जी एए ने भारत को किए गए अपने निर्यातों के बारे में ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं । तथापि चूंकि कंपनी ने पूर्ण सहयोग नहीं दिया है, इसलिए इस मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा असहयोगी निर्यातकों के मामले में अपनाई जाने वाली परिपाटी के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया जाए ।
- (9) कृपया पाटन रोधी नियमों पर ध्यान दिया जाए जिनमें यह व्यवस्था की गई है कि जहां एक से अधिक देशों से किसी उत्पादन के आयात की पाटनरोधी जांच की जाती है वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप में मूल्यांकन करेंगे । अनुरोध है कि मौजूदा मामले में नियम के तहत सभी शर्तों पूरी होती है । अतः संबद्ध देशों के आयातों से घरेलू उद्योग को संचयी रूप से हुई क्षति का निर्धारण करना उचित होगा ।

(ii) निर्यातकों आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

- (1) मै0 ए एम ई लि0, बड़ौदा की एकमात्र याचिकाकर्ता और विटामिन सी का एकमात्र उत्पादक है, परन्तु उनके पास फर्मेन्टेशन प्रक्रिया द्वारा विटामिन सी का उत्पादन करने के लिए नई तथा उन्नत प्रौद्योगिकी नहीं है । विश्वभर में विनिर्माता मै0 रेक्विट, फ्रांस से सर्बिटोल कच्ची सामग्री का आयात करते हैं अथवा स्थानीय रूप से विनिमिति सोर्बिटोल का प्रयोग करते हैं, तब 2 कोटो ग्लूकोनिक एसिड का उत्पादन करने के लिए संघटकों को मिलाने के बाद फर्मेन्टेशन करते हैं । यह एक मुख्य निविष्टि है जिससे याचिकाकर्ता विटामिन सी बनाने की सोचता है । उक्त तथ्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट है कि विश्व में प्रमुख उत्पादकों की उत्पादन लागत याचिकाकर्ता की कंपनी से काफी कम है ।
- (2) यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो यूरोपीय संघ तथा रूस से आयात अलाभकारी हो जाएंगे और वे बिलकुल बन्द हो जाएंगे । चीन तथा जापान के विटामिन सी पर पाटनरोधी शुल्क है जिसके लिए याचिकाकर्ता ने उसको बढ़ाने के लिए समीक्षा हेतु आवेदन दायर किया है । इसलिए याचिकाकर्ता की दलील यह सिद्ध करने के लिए है कि विश्व के सभी विनिर्माता अपने विटामिन सी का पाटन केवल भारत में करना चाहते हैं जो पूर्ण रूप से गलत और अतार्किक प्रतीत होती है ।

- (3) विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र विस्तार को बढ़ाकर उसमें 2-केटो ग्लूकोनिक एसिड भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि उक्त उत्पाद को विटामिन के समनुरूप होता है। यह उत्पाद भी समान आई टी सी वर्गीकरण के भीतर आता है। मै0 ए एस ई स्वयं इस उपान्तिम उत्पाद अर्थात् 2-केटो ग्लूकोनिक एसिड का बड़ी मात्रा में आयातक है जिसे एक बहुत ही आसान तरीके द्वारा विटामिन सी में बदल दिया जाता है। प्रौद्योगिकी कीमत और उत्पादन प्रक्रिया अनुसार इस मध्यवर्ती उत्पाद और अंतिम उत्पाद अर्थात् विटामिन सी के बीच सीधा संबंध है। विटामिन सी का विनिर्माण 16 से अधिक चरणों वाली एक व्यापक प्रक्रिया के जरिए किया जाता है। विटामिन सी के विनिर्माण के चरणों से एक चरण में 2-केटो ग्लूकोनिक एसिड का उत्पादन भी शामिल होता है। 2-केटो ग्लूकोनिक एसिड और विटामिन सी के बीच एक सीधा सह-संबंध है। पाटनरोधी कानून के लिए यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि जो याचिकाकर्ता आयात करता है वह पाटनरोधी संरक्षण की मांग कर सकता है।

तदनुसार याचिकाकर्ता को या तो पाटनरोधी संरक्षण प्राप्त करने से वंचित किया जाए या वैकल्पिक तौर पर इसे विटामिन सी के समान वस्तु माना जाए और समान वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए।

4. हमारा अनुरोध है कि हमारे आयातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है। भारत में कथित उत्पाद की कुल मांग 1200 टन से अधिक है, जबकि शिकायतकर्ता जो एकमात्र उत्पादक है, की स्थापित क्षमता केवल 430 टन की है जिससे एकाधिकार की स्थिति न्यायोचित ठहरती है। इस मांग में वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि, शिकायतकर्ता अपनी स्थापित क्षमता के 100 % का उत्पादन करता है और उसे बेचता है। फिर भी, वह बाजार की जरूरत अथवा मांग पूरी नहीं कर सकता है। इसलिए भारत में विटामिन-सी की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात करने पड़ते हैं। चूंकि शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता घरेलू मांग पूरी करने में असमर्थ है, इसलिए उसके लिए यह अनुचित है कि वह पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग कर आयातों को सीमित करे।

5. घरेलू उद्योग को हुई क्षति स्वयं पहुँचायी गई क्षति है। शिकायतकर्ता का संयंत्र बहुत छोटा है और अव्यवहार्य है तथा बड़े पैमाने पर किफायतों की व्यवस्था नहीं है। शिकायतकर्ता की लघु स्थापित क्षमता से कथित उत्पाद की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने घरेलू उद्योग की आधी मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त उत्पादन भी नहीं किया है। यह अव्यवहार्य संयंत्र का आकार है जो घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचा रहा है।

6. मैसर्स साराभाई भी यह प्रकट करने में विफल रहा है कि वह अपनी कैप्टिव खपत के लिए आयातित सामग्री को काफी कम लागत पर लाए हैं जिसके फलस्वरूप अपनी खपत से कम माल उठाया गया है जिससे उत्पादन में घाटा हुआ है।

7. उनके उत्पादन और बिक्री में जो घाटा हुआ है उसका मुख्य कारण एकाधिकार की स्थिति है जो प्रतिबंधित आयातों और खराब व्यापार नीतियों की वजह से पूर्ववर्ती समय में अस्तित्व में थी।

8. सभी प्रमुख विनिर्माताओं की पिछले तीन वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कमोबेश अपरिवर्तित रही हैं। हमें इस बात का आश्चर्य है कि सरकार ने साराभाई की अभूतपूर्व ऊँची कीमतों के कारणों पर विचार क्यों नहीं किया है जो कि सभी प्रमुख विनिर्माताओं की वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से 2 - 1/2 गुना अधिक है।

9. याचिकाकर्ता ने ई यू में सामान्य मूल्य की पुष्टि करने के प्रयोजन से आयरलैंड के एक विनिर्माता के साक्ष्यों पर विश्वास किया है। सार्वजनिक सुनवाई में, ई यू के सहयोगी निर्यातकों ने यह पुष्टि करने के लिए अपने बयान दर्ज कराए कि आयरलैंड में विटामिन सी का कोई उत्पादक नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि ई यू से होने वाले आयातों पर लगाए जाने वाले शुल्क से संबंधित सम्पूर्ण कार्रवाई को शुरु से रद्द कर देना चाहिए।

10. घरेलू उद्योग को हुई क्षति पाटन के कारण नहीं हुई है बल्कि क्षति के कुछ अन्य कारण हैं क्योंकि याचिकाकर्ता की विनिर्माण प्रक्रिया पुरानी है। स्वीकृत प्रक्रिया अब 2-केटो ग्लूकेनिक एसिड से शुरु होती है न कि सोर बिट्रल से। इससे विटामिन सी के विनिर्माण के लिए अपेक्षित चरणों में कमी आती है। याचिकाकर्ता की उत्पादन लागत भी विद्युत आदि की वजह से अधिक है।

याचिकाकर्ता की स्वीकारोक्ति में भी भारत में विटामिन सी के आयात अत्यधिक प्रतिबंधित हैं और आयात शुल्क अधिक है। तथापि, 90 के दशक के मध्य में जब शुल्कों में सपाट दर से कमी की गई थी और आयातों पर से प्रतिबंध हटा लिए गए थे तब आयातों में वृद्धि होनी शुरु हुई थी। आयात शुल्कों में कमी और व्यापार बाधाओं को हटाने के कारण अन्य विनिर्माताओं, जैसे- जयंत विटामिन्स और जिंदल ड्रग्स लिमिटेड ने या तो अपने उत्पादन कार्यक्रम बंद कर दिए थे या उन्हें धीरे-धीरे बंद कर रहे थे।

- 11 (i) प्राधिकारी ने प्रशासनिक, बिक्री, सामान्य खर्चों और ब्याज, मूल्यहास और लाभ के तत्व और घरेलू बाजार में बिक्री कीमत की अनदेखी समेत उत्पादन लागत के आधार पर बी ए एस एफ के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने में गलती की है। (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने बी ए एस एफ द्वारा प्रस्तुत लागत आंकड़ों का सत्यापन नहीं किया है। निर्यातक ने यह अनुरोध किया है कि :

जर्मनी में बिक्री कीमत वस्तुतः प्रातिनिधिक है।

यदि जर्मनी में बिक्री कीमत की किसी कारण से अनदेखी की जानी थी तो अन्य यूरोपीय संघ के देशों को होने वाली बिक्री की कीमत पर विचार किया जाना चाहिए था और ऐसा करते समय यह मानना चाहिए कि यूरोप में कीमतों का निर्धारण चीन से यूरोप में हुए आयातों के अनुसार किया जाता है।

- (ii) सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी बिक्रियों की अनदेखी कर सकते हैं, यदि उनकी बिक्री यूनिट कीमत पर की जाती है जो एकक लागत से कम है अर्थात् उत्पादन लागत जमा बिक्री सामान्य और प्रशासनिक व्यय (सी जी एंड ए) और निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हों-

- (क) ऐसी बिक्रियां ऐसी कीमतों पर की गई हैं जिनसे समूची लागत की वसूली एक उचित समायावधि के भीतर नहीं की जा सकती है; और
- (ख) ऐसी बिक्रियां बढ़ी हुई अवधि के भीतर पर्याप्त मात्रा में होती रहती है।

यह स्वीकार किए बिना यह मानना कि उत्पादन लागत से नीचे की गई कथित बिक्रियों की सही गणना की गई है, ऐसी कीमतों पर नहीं की गई है जिससे उचित समायावधि के भीतर सभी लागतों की वसूली नहीं की जा सकती है। बी ए एस एफ ए जी ने क्षमता एवं प्रौद्योगिकी सुधारों के विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति की है जिसके फलस्वरूप लागतों में पर्याप्त गिरावट आएगी और लाभप्रदता में वृद्धि होगी और कंपनी को पूरी लागत वसूलने में मदद मिलेगी। यह लाभ शीघ्र ही

उत्पन्न होने वाला है। यह तथ्य जो अनिवार्य है, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जर्मनी अथवा यूरोपीय संघ में हुई बिक्री की कीमत की अनदेखी करने के लिए किसी निष्कर्ष पर पहुँचने हेतु उपेक्षा की गई है।

(ग) उठाए गए मुद्दों की जांच

निर्यातक, आयातक, याचिकाकर्ता और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों की जांच की गई है और उन नियमों जिनका इस मामले में प्रभाव पड़ सकता है, के संदर्भ में उठाए गए मुद्दों पर विचार किया गया है और अधिसूचना में उचित स्थानों पर उन पर कार्रवाई की गई है।

(घ) प्राधिकारी द्वारा आवश्यक तथ्यों का प्रकटीकरण

जो विचार प्रकटीकरण विवरण के प्रत्युत्तर में व्यक्त किए गए हैं उन पर इसके नीचे संगत पैराओं में उस सीमा तक चर्चा की गई है जिस सीमा तक वे नियमानुसार संगत हैं और इस मामले पर कोई प्रभाव डालते हैं।

(क) याचिकाकर्ता द्वारा की गई टिप्पणियां

(i) याचिकाकर्ता का यह दावा कि शुल्क उस उत्पाद पर लगाया जाता है जिसे विचाराधीन उत्पाद के रूप में वर्णित किया जाता है और इसे समान वस्तु पर लागू नहीं किया जा सकता। समान वस्तु का मुद्दा स्थिति, घरेलू उद्योग और सामान्य मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में संगत है। विचाराधीन उत्पाद जांच अवधि में भारतीय बाजार में पाटित उत्पाद रह जाता है। इसे समान वस्तु पर लागू नहीं किया जा सकता।

(ii) निर्दिष्ट प्राधिकारी को मै0 बीएएसएफ द्वारा कीमत-बचन पत्र के बारे में किए गए प्रस्ताव के संबंध में याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक से तब तक कोई कीमत संबंधी वचन-पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें निर्यातक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर टिप्पणियां देने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता।

(iii) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हाल ही में जापान एवं चीन से हुए आयातों के लिए समान उत्पाद की समीक्षा जांच पूरी की है। उस मामले में भिन्न-भिन्न आधार पर शुल्कों की सिफारिश की गयी है। याचिकाकर्ता इस मामले में भी निर्दिष्ट प्राधिकारी से भिन्न-भिन्न शुल्क^{की} सिफारिश करने का अनुरोध करते हैं ताकि घरेलू उद्योग के हित की पर्याप्त सुरक्षा की जा सके और सभी आयात एक समान स्तर पर हों।

ख. आयातकों द्वारा की गई टिप्पणियां

(i) प्रकटन विवरण-पत्र में केवल अंतिम निष्कर्षों पर पहुँचने की प्रणाली का उल्लेख किया गया है। प्रकटन विवरण-पत्र में किसी तथ्य अथवा विशलेषण का उल्लेख नहीं किया गया है।

(ii) ई यू के सहयोगी निर्यातक मै0 बीएएसएफ के सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या घरेलू बाजार में बिक्री^{क्ष} उचित समयावधि से अधिक के लिए उत्पादन लागत कम पर की गई थीं।

प्राधिकारी द्वारा आवश्यक तथ्यों के प्रकटन के संबंध में दी गई टिप्पणियों की जांच

हितबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों की जांच की गई है, उन पर विचार किया गया है और जहां उचित पाया गया है, उन पर इस अधिसूचना में संगत पैराग्राफों में कार्रवाही की गयी है।

जहां तक आवश्यक तथ्यों के प्रकटन का संबंध है प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार निदेशालय की संगत प्रक्रिया का अनुपालन किया है।

८. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद रुस और यूरोपीय संघ के मूल के या वहां से निर्यातित विटामिन सी है। विटामिन सी सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के सीमाशुल्क उपशीर्ष 2936.27 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

९. याचिकाकर्ता की "घरेलू उद्योग" संबंधी स्थिति:

यह याचिका मै0 अम्बालाल साराभाई एंटरप्राइजिस लि0 द्वारा दायर की गयी है जिसका पंजीकृत कार्यालय वाडी वाडी, बड़ौदा-390007 में है। याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। एक अन्य कंपनी मै0 जयंत विटामिन लि0, जिसने भारत में विटामिन सी के विनिर्माण हेतु क्षमताओं का सृजन किया था, ने अब अपना प्रचालन बंद कर दिया है। अतः याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु के कुल उत्पादन के लिए जिम्मेवार है और वह नियमों के अंतर्गत यथापेक्षित घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के अपेक्षित मापदण्ड को पूरा करता है।

याचिकाकर्ता की स्थिति के संबंध में एक तर्क यह दिया गया है कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग का अंग बनने के अयोग्य है क्योंकि वह 2 केजीए जो कि विटामिन सी के लिए अंतिम चरण की सामग्री है और इसलिए वह विटामिन सी के समान वस्तु है, का आयातक है। तथापि, प्राधिकारी यह पाते हैं कि 2 केजीए और विटामिन सी उत्पाद वाणिज्यिक और ताकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं है और पूर्ववर्ती उत्पाद पश्चात्तवर्ती उत्पाद के विनिर्माण हेतु केवल एक मध्यवर्गी उत्पाद है। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा आयातित 2केजीए को विटामिन सी के समान वस्तु के रूप में विचार नहीं किया गया है। अतः, प्राधिकारी यह मानते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए 2 केजीए के आयात विटामिन सी के आयातक के रूप में मै0 अम्बालाल साराभाई एंटरप्राइजिस लि0 की परिभाषा में नहीं आते हैं और उसे नियमों के तहत घरेलू उद्योग के क्षेत्र-विस्तार से बाहर नहीं रखा जाता है।

१०. समान वस्तुएं

प्रारंभिक निर्धारण में प्राधिकारी ने यह माना था कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए विटामिन सी और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु की विशेषताएं एक समान हैं और उन्हें समान वस्तुओं के रूप में समझा जाना चाहिए। प्राधिकारी ने यह भी निर्धारित किया कि याचिकाकर्ता और इन देशों के उत्पादकों द्वारा अपनायी गयी प्रौद्योगिकी में कोई खास अंतर नहीं है। यद्यपि प्रत्येक विनिर्माता उपलब्ध सुविधाओं और जरूरतों के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है।

2 केजीए को विटामिन सी के समान वस्तु मानने के बारे में कुछेक हितबद्ध पक्षों द्वारा मुद्दे उठाए गए। प्राधिकारी ने उपरोक्त पैरा 5 में पहले यह स्पष्ट कर दिया है कि 2 केजीए विटामिन सी के विनिर्माण हेतु एक मध्यवर्ती उत्पाद है अतः इसे समान वस्तु के रूप में नहीं माना जा सकता।

इस बात को देखते हुए प्राधिकारी यह पुष्टि करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विटामिन सी और संबद्ध देशों से आयातित विटामिन सी संगत नियमों के अर्थ के भीतर समान वस्तुएं हैं।

2. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन - ई.यू.

प्राधिकारी ने धारा 9(क)(1)(ग) में दिए गए नियमों के अनुसार किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य की जांच की है। इस मामले में जर्मनी के केवल मै0 बीएएसएफ तथा मै0 मर्क केजीए ने उत्तर दायर किया है। सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

1. मै0 बीएएसएफ, जर्मनी

सामान्य मूल्य:

(क) प्राधिकारी द्वारा घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के साथ-साथ जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री के संबंध में निर्यातकों द्वारा किए गए दावों का सत्यापन किया गया है। उल्लेखनीय है कि ये बिक्रियां ऐसी कीमतों पर की गयी हैं जिससे उचित समयावधि के भीतर पूरी लागत की प्राप्ति नहीं होती है और ऐसी बिक्रियां भारी मात्रा में की गयी हैं। निर्यातक ने यह भी स्वीकार किया है कि कंपनी ने घरेलू बाजार में घाटे पर अर्थात् उनकी उत्पादन लागत से कम पर विटामिन सी की बिक्री की है।

(ख) उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी प्रशासनिक, बिक्री, सामान्य खर्चों और उचित लाभ मार्जिन समेत उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना उचित समझते हैं। चूंकि सामान्य मूल्य, बिक्री, सामान्य प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभ मार्जिन समेत उत्पादन लागत पर आधारित होता है इसलिए प्राधिकारी ने किसी अन्य समायोजन पर विचार नहीं किया है।

(ग) आयरिश उत्पादक की बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के बारे में मै. बीएएसएफ तथा आयातकों द्वारा दिए गए तर्कों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कि जर्मनी और यू.के., यूरोपीय संघ के अंग हैं और उनका सामान्य सीमाशुल्क भूभाग है, समूचे यूरोपीय संघ में कीमतें अवश्यमेव एकसमान रहनी हैं, मामला शुरू करने के लिए इस आंकड़े पर प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में विश्वास किया है। चूंकि, बाद में कुछेक निर्यातकों ने उत्तर दिया है इसलिए प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना के आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले हैं।

(घ) जहां तक क्षमता विस्तार और प्रौद्योगिकी सुधार, जिसके परिणामस्वरूप जांच अवधि के बाद लागत में पर्याप्त कमी आयी है, का संबंध है, प्राधिकारी ने इस मामले में पाटनरोधी नियमों के अनुसार जांच की है और वह स्पष्ट करते हैं कि जांच अवधि से संबंधित सूचना इस मामले के लिए संगत है।

निर्यात कीमत

निर्यातक मै. बीएसएफ ने जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए सम्बद्ध वस्तुओं के निर्यात के कारोबार-वार ब्यौरे प्रस्तुत किए। सत्यापन के पश्चात मै. बीएसएफ के मामले में निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए भारत और सीआईएफ निर्यात कीमत पर विचार किया गया। निर्यात बिक्री, विदेशी मालभाड़ा, अन्तर्राज्यीय भाड़ा, हैंडलिंग प्रभार और पैकिंग प्रभार के संबंध में निर्यातक द्वारा दावा किए गए समायोजनों की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई और कारखाना स्तर पर निर्यात कीमत निकालने के लिए इसकी अनुमति देने पर विचार किया गया।

असहयोगी निर्यातकों के संबंध में डम्पिंग मार्जिन:

2. मै. मैर्क के जीएए, जर्मनी

सामान्य मूल्य

मै. मैर्क के जीएए ने न तो अपनी घरेलू बिक्री के कारोबार-वार ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं और नहीं उन्होंने विटामिन सी की उत्पादन लागत प्रस्तुत की है। निर्यातक ने कभी भी इस बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आगे मांगी गई जानकारी का जवाब नहीं दिया है और न ही सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया। प्रारम्भिक निष्कर्षों के पश्चात कोई लिखित सूचना प्रस्तुत की।

उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी ने मै. मैर्क के जीएए को असहयोगी निर्यातक माना है। अतः प्राधिकारी ने मै. मैर्क के जीएए के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण उचित उपलब्ध सूचना के आधार पर किया है।

निर्यात कीमत:

निर्यातक मै. मैर्क के जीएए ने जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए सम्बद्ध वस्तुओं के निर्यात के कारोबार-वार ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं। निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए भारत और सीआईएफ निर्यात कीमत पर विचार करने का प्रस्ताव है। निर्यातक ने सीआईएफ निर्यात कीमत से किसी समायोजन को प्रकट नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी ने नियम 6(8) अर्थात् उचित उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

झ.

अन्य निर्यातकों के मामले में डम्पिंग मार्जिन

प्राधिकारी ने पाया है कि यूरोपीय संघ से निर्यातों की मात्रा मै. बीएएसएफ और मै. मैर्क के जीएए दोनों द्वारा बताई गई निर्यात मात्रा से अधिक है। इसलिए, यूरोपीय संघ के अन्य निर्यातकों के संबंध में प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ के सहयोगी निर्यातकों के संबंध में मै. मैर्क के जीएए की डम्पिंग मार्जिन पर आधारित मार्जिन पर विचार करना उपयुक्त समझा है।

ज. रूस से अन्य निर्यातकों के मामले में डम्पिंग मार्जिन:

9(क) प्राधिकारी ने नियमों के अनुसार रूस के निर्यातकों को जांच से संबंधित सूचना और अन्य टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया। प्राधिकारी ने भारत में रूसी दूतावास को भी लिखा। तथापि सम्बद्ध देश के किसी भी निर्यातक ने सूचना के लिए किए गए प्राधिकारी के निवेदन का जवाब नहीं दिया है।

(ख) याचिकाकर्ता द्वारा सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में किए गए दावे का किसी हितबद्ध पार्टी (पार्टियों) द्वारा विरोध नहीं किया गया है। इसलिए प्राधिकारी ने नियम 6(8), यानि उचित उपलब्ध सूचना के आधार पर कार्रवाई की है।

(ग) जांच की शुरुआत के समय सामान्य मूल्य का निर्धारण रूस में विटामिन-सी की परिकलित उत्पादन लागत जैसी की याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई है के आधार पर किया गया है।

प्राधिकारी ने उपयुक्त समायोजनों के पश्चात सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इसी आधार पर विचार किया है।

(घ) निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता द्वारा संकलित की गई सूचना के आधार पर किया गया है। भारत और निर्यात कीमत को कमीशन, बीमें, अन्तराज्यी भाड़े, विदेशी भाड़े पैकिंग तथा हैडलिंग प्रभारों के लिए समायोजित किया गया है, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया है।

ट. तुलना से संबंधित नियमों में निम्नानुसार प्रावधान है:

*पाटन का मार्जिन निकालते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच एक उचित तुलना करेगा। यह तुलना व्यापार के एक समान स्तर पर, सामान्यतया कारखाना द्वार स्तर पर की जाएगी और यथा-संभव उसी समयावधि के दौरान की गई बिक्रियों के संबंध में की जाएगी। जो अंतर कीमत तुलनीयता यपर प्रभाव डालते हैं, उनके लिए प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर उचित छूट दी जाएगी। उक्त अंतर में

बिक्री की शर्तें, कराधान, व्यापार के स्तर, मात्राएं, भौतिक विशेषताएं तथा अन्य ऐसे अन्तर शामिल हैं जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं । "

1 ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर अलग-अलग निर्यातकों और विशिष्ट देशों के संदर्भ में पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	देश/निर्यातक	पाटन मार्जिन %
1.	यूरोपीय संघ	
	1. मै. बीएसएफ जर्मनी (मै. बीएसएफ स्वास्थ्य एवं पौष्टिक डेनमार्क मूल से)	49.20
	2. अन्य निर्यातक	134.73
2.	रूस	
	सभी निर्यातक	122.82

ठ. क्षति और कारणात्मक संबंध

1. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जाँच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या पाटित आयातों के कारण भारत में समान वस्तुओं की कीमत की तुलना में कीमत में कोई उल्लेखनीय गिरावट आई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों से कीमतों में अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक गिरावट आई है या कीमत वृद्धि में अन्यथा रुकावट आई है जो कि अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ गई होती ।
2. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच के लिए उपर्युक्त नियमों के अनलग्नक 11 (iv) के अनुसार प्राधिकारी ने उन विषयों पर विचार किया जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री आय, डम्पिंग की मात्रा तथा मार्जिन इत्यादि ।
3. प्राधिकारी ने पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों अर्थात् गैर-किफायती संयंत्र आकार, निष्क्रियता, कुप्रबंधन अथवा कोई अन्य कारक जोकि उपर बंझाए गए हैं और जो घरेलू उद्योग को साथ-साथ ही क्षति पहुँचा सकते हैं, की भी जांच की ।

घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण सभी आवश्यक कारकों जैसे जांच अवधि के दौरान कच्ची सामग्री का उपयोग, क्षमता का उपयोग, निश्चित खपत इत्यादि और वास्तविक खर्चों का उपयुक्त विश्लेषण करके किया गया है, जिसमें निवेश और क्षमता उपयोग भी शामिल है । घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत उत्पादन की इष्टतम लागत पर विचार करके और घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई पूंजी पर प्राप्त आमदनी पर विचार करके निर्धारण की गई है ।

दु. क्षति संबंधी निष्कर्ष

1. प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि

(क) उत्पादन तथा क्षमता उपयोग:-

याचिकाकर्ता कम्पनी का उत्पादन 1996-97 में हुए 468.961 मी. टन से गिरकर 1997-98 में 303.713 मी. टन रह गया। जांच अवधि में लगभग 1200 मी. टन की कुल मांग की तुलना में और आगे गिरकर 283.842 मी. टन हो गया।

कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान प्राप्त किया गया 109% का क्षमता उपयोग वित्तीय वर्ष 1997-98 में गिरकर 71% रह गया जो जांच अवधि के दौरान गिरकर वार्षिक आधार पर 66% हो गया।

(ख) बिक्री मात्रा:-

याचिकाकर्ता कम्पनी की बिक्री 1996-97 के 413.694 मी. टन से गिरकर 1997-98 के दौरान 269.457 मी. टन और आगे वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान गिरकर 234.792 टन हो गई।

(ग) बिक्री वसूली:-

याचिकाकर्ता कम्पनी की औसत बिक्री वसूली 1996-97 के दौरान *** रु./किग्रा. थी जो वर्ष 1997-98 में मामूली बढ़कर *** रु./किग्रा. हो गई। जांच अवधि के दौरान बिक्री वसूली में एक तेजी से गिरावट हुई और यह *** रु./किग्रा. थी। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता कम्पनी की बिक्री वसूली उसकी उत्पादन लागत से कम थी।

(घ) लाभप्रदता

31 मार्च, 1997 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान विटामिन-सी के कारोबार में कम्पनी का घाटा 64.75 लाख था जो 31 मार्च, 1998 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बढ़कर 530.13 लाख रूपए हो गया। घाटा आगे बढ़कर वर्ष 1998-99 के दौरान 573.50 लाख रूपए हो गया।

(ड.) सम्बद्ध देशों से आयातों में वृद्धि

1996-97 के दौरान यूरोपीय संघ से हुए आयात 42.8 मी. टन से बढ़कर 1997-98 में 114.53 मी. टन हो गए और 1998-99 के दौरान मामूली गिरकर 107.581 मी. टन हो गए।

पिछले वर्षों के शून्य आयातों की तुलना में रूस से हुए आयात जांच अवधि के दौरान 30 मी. टन थे।

(च) संबद्ध देशों से हुए आयात की कीमतों में गिरावट

वर्ष 1996-97 के दौरान ई यू से हुए आयात की कीमत 3.66 अमरीकी डालर/किग्रा. सी आई एफ थी, जो वर्ष 1997-98 के दौरान 2.66 अमरीकी डालर/किग्रा. सी आई एफ तक गिर गई और वर्ष 1998-99 के दौरान सी आई एफ कीमत में 2.78 अमरीकी डालर/किग्रा. की मामूली बढ़ोतरी हुई। जांच अवधि के दौरान रूस से हुए आयात की सी आई एफ कीमत 2.6 अमरीकी डालर/किग्रा. थी। प्राधिकारी मानते हैं कि आयातों की ऐसी कम कीमत के कारण घरेलू उद्योग डी पी सी ओ कीमत वसूल करने की स्थिति में नहीं था।

(च) अंतिम स्टॉक

वर्ष 1996-97 के दौरान याचिकाकर्ता का अन्तिम स्टॉक 1.862 मी.टन का था, जो वर्ष 1997-98 के दौरान बढ़कर 4.345 मी.टन हो गया और जांच अवधि के दौरान यह घटकर 3.95 मी.टन हो गया।

(छ) रोजगार

याचिकाकर्ता ने कुछ हद तक घाटा कम करने के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान अपने 482 कर्मचारियों को कम करके जांच अवधि में उनकी संख्या 311 कर दी।

2. अतः प्राधिकारी उपरोक्त से यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम पर हुए हैं। इसके अलावा, भारत में आयात घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत से कम कीमत पर हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता अपने उत्पाद को अपनी क्षतिरहित कीमत से काफी कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य हुआ था जिसके कारण याचिकाकर्ता को वित्तीय घाटा हुआ था। याचिकाकर्ता को क्षमता उपयोग के स्तर को बढ़ाने से भी रोका गया था।

ये मापदण्ड सामूहिक और संचयी रूप से यह प्रदर्शित करते हैं कि याचिकाकर्ता को आयातों के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

६. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

1. सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य ऐसे पाटन को समाप्त करना है जिससे याचिकाकर्ता कंपनियों को नुकसान हो रहा है तथा भारतीय बाजार में ऐसी खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की पुनःस्थिति लाना है, जो कि देश के सामान्य हित में है।
2. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों का कीमत स्तर प्रभावित हो सकता है और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है। किन्तु, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी विशेषकर तब, जब पाटनरोधी शुल्क की लेवी उस राशि तक ही सीमित कर दी जाए जो कि याचिकाकर्ता कंपनी को हुए नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों के इस्तेमाल से पाटन द्वारा प्राप्त किए गए अनुचित लाभ समाप्त होंगे। याचिकाकर्ता कंपनी के ह्रास को रोका जाएगा और विटामिन-सी के उपभोक्ताओं के लिए होने वाले आयात किसी प्रकार कम नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
3. याचिकाकर्ता कंपनी को हुई क्षति दूर करने के लिए आवश्यक पाटनरोधी शुल्क की मात्रा को सुनिश्चित करने के निमित्त प्राधिकारी याचिकाकर्ता कंपनी के लिए क्षमता उपयोग के ईष्टतम स्तर पर उत्पादन की अधिकतम लागत पर विचार करके भारत में याचिकाकर्ता कंपनी के लिए विटामिन-सी की क्षति रहित कीमत पर विश्वास करते हैं।

न निष्कर्ष

20. प्राधिकारी उपरोक्त पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:-
- (क) संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विटामिन-सी का सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत को निर्यात किया गया है, जिसके कारण पाटन हुआ है।
- (ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- (ग) रूस तथा ई यू के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

त अन्तिम निष्कर्ष

प्राधिकारी उपरोक्त पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:-

- (क) अतः प्राधिकारी रूस और ई यू के मूल के या वहाँ से निर्यातित अध्याय 29 (सीमाशुल्क उपशीर्ष 2936.2700) के अंतर्गत आने वाले विटामिन सी के सभी आयातों पर निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।
- (ख) इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुँच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन सीमाशुल्क विभाग द्वारा यथा आकलित निर्धारणीय मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3, 3 क, 8 ख, 9 तथा 9 क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर, सभी प्रकार के सीमा शुल्क शामिल होंगे।
- (ग) पाटन मार्जिन के बराबर अथवा ऐसी कम पाटनरोधी शुल्क की धनराशि की सिफारिश पर विचार किया गया था जिसे यदि वसूल किया जाता है तो उसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी। इस प्रयोजनार्थ अलग-अलग निर्यातकों के लिए आयातों की पहुँच मूल्य की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षति रहित बिक्री कीमत के साथ की गई थी। जहां कहीं यह अंतर पाटन मार्जिन से कम पाया गया था वहां पाटन मार्जिन से कम शुल्क की सिफारिश की गई है।
- (घ) तदनुसार संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विटामिन-सी के सभी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए। पाटनरोधी शुल्क नीचे कालम तीन में दी गई धनराशि और डालर प्रति किग्रा. में आयातों के पहुँच मूल्य के बीच का अंतर होगा।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	धनराशि अमरीकी डालर/किग्रा.
1.	ई यू	
	1. मै. बी ए एस एफ जर्मनी (मै. बी ए एस एफ स्वास्थ्य एवं पौष्टिक डैनमार्क मूल से)	11.29
	2. अन्य निर्यातक	12.67
2.	रूस	
	सभी निर्यातक	12.67

(ड.) उपरोक्तानुसार प्राधिकारी 17 जनवरी, 2000, के प्रारंभिक निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

(च.) इस आदेश के खिलाफ कोई अपील उपरोक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जा सकेगी।

रति विनय झा, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th August, 2000

FINAL FINDINGS

Sub:- Anti Dumping investigation concerning imports of Vitamin-C from Russia and European Union(EU) – Final Findings.

26/1/99-DGAD - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof -

A. PROCEDURE:

The procedure described below has been followed

- i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) notified preliminary findings vide notification dated the 17th January, 2000 on anti-dumping investigation concerning imports of Vitamin-C(hereinafter also referred to as subject goods) from European Union(EU) and Russia(hereinafter referred to as subject countries)and requested interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;
- ii) The Authority forwarded a copy of the preliminary findings to known interested parties, who were requested to furnish their views, if any, on the preliminary findings within forty days of the date of the letter,
- iii) The Authority also forwarded a copy of the preliminary findings to the Embassy of Russia and the Delegation of European Union (EU) in New Delhi with a request that the exporters and other interested parties may be advised to furnish their views on the preliminary findings in the time frame as stipulated in (i) and (ii) above,
- iv) The Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally All parties presenting their views orally were requested to file written submissions of the views expressed orally. The parties were

advised to collect copies of the views expressed by opposing parties and offer rebuttals, if any. The written submissions thus received from interested parties have been considered by Designated Authority in this finding.

- (v) The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties, for inspection, upon request,
- (vi) Arguments raised by interested parties before announcing of preliminary findings, which have been brought out in the preliminary findings notified earlier have not been repeated herein for sake of brevity. However, the arguments raised by the interested parties after preliminary findings have been appropriately dealt in this findings,
- (vii) Verification of exporters' data was carried out by the Authority to the extent it was feasible. A team of Officers of the Directorate carried out verification of the data at the exporters premises viz. M/s. BASF Plant & Corporate Office at Denmark and Germany respectively;
- (viii) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to the known interested parties on 21 07 2000 and comments received on the same have also been duly considered in these findings
- (ix) ***** in the Notification represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by Authority under the Rules

B. VIEWS OF PETITIONER, EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES AND EXAMINATION BY AUTHORITY:

The petitioner, exporters and importers have expressed their views, and the same are briefly mentioned below. The arguments expressed by the exporters and importers, which are similar in nature, have not been repeated for sake of brevity.

(i) **PETITIONERS' VIEWS:**

- (1) As per decision of Hon'ble CEGAT recently the duty in a number of appeals have been modified in terms of US \$. The Designated Authority has also recommended duties in terms of US\$ in a few recommendations issued recently. It is, therefore, requested that the duties be recommended in terms of US\$ in the final determination.
- (2) Though there are a number of exporters in the subject countries, only two exporters responded. Even out of the limited response received by the Designated Authority, it was found at the time of the hearing that one of the exporters, M/s Merck did not participate in the oral hearing, which indicates lack of interest and cooperation. It is requested that M/s Merck may not be permitted to make any submissions in writing, as the opportunity for written submissions is only to those interested parties who appeared for the hearing and made submissions.
- (3) M/s BASF has provided details of sales in the home market as well as cost of production. Information provided by the company shows that the company has sold Vitamin-C at loss in the home market. In fact, at the time of the oral hearing also, the representative of the exporter clearly admitted that they were incurring losses on their sales of Vitamin-C. The Designated Authority has determined normal value on the basis of cost of production of the company in the preliminary findings.
- (4) After analysing the non-confidential submission of the company especially the cost of production we found that M/s BASF has claimed abnormally low per unit cost on account of a number of item of costs, prominent among which are variable product cost, administration cost and interest cost. It may be recalled that the representative of the company laid heavy emphasis on R&D at the time of the oral hearing. We are also aware that BASF incurs substantial expenditure on R&D. However, the cost of production claimed by the company does not seem to provide adequately for expenses on this account.
- (5) In view of the above and confidential nature of the information filed by the company, it is submitted that the information filed by the company should be scrutinised in detail before arriving at final recommendations. The Designated Authority may kindly verify the various claims of the exporter before adopting the same for final determination.
- (6) M/s Merck KgaA has neither provided transaction-wise details of the sales made in the home market nor provided details of the cost of production.

The information filed by the company is clearly insufficient to determine normal value of the company. It is requested that the company should be treated as non-cooperative and the Designated Authority may please construct cost of production of Merck based on the information provided by us with regard to costs incurred for production of Vitamin-C for the purpose of determination of normal value

- (7) M/s BASF has provided details about their exports to India. The company has claimed adjustment from the export price on account of inland freight, overseas freight and packing. However, no adjustment has been disclosed on account of insurance and port expenses. It is submitted that the export price to be adjusted for the expenses on these accounts.
- (8) M/s Merck KGaA has provided details about their exports to India. However, since the company has not fully cooperated, the export price in this case be determined on the basis of the practice being followed by the Designated Authority in case of non-cooperative exporters.
- (9) Attention is requested to Anti Dumping Rules, which provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti dumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports. It is submitted that all the conditions under the rule are satisfied in the present case. It would, therefore, be appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from imports from the subject countries.

(ii) **VIEWS OF EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES:**

- (1) M/s ASE Limited, Baroda, is the only petitioner and sole producer of Vitamin-C but they do not have new and sophisticated technology to produce Vitamin-C by fermentation process. All over the world manufacturers import the raw material Sorbitol from M/s Rouquette, France or use locally manufactured Sorbitol, then do the fermentation after adding ingredients to produce 2-Keto Gluconic Acid which is a key intermediate from which the petitioner intends to manufacture Vitamin-C. By considering the said fact it is evident that the cost of production by major producers in the world is much lower than the petitioner's co.
- (2) If the Anti-Dumping Duty is imposed, the imports from European Union and Russia will be uneconomical and it would stop completely. There is Anti-Dumping Duty on Chinese and Japanese Vitamin-C for which the petitioner has filed review application to increase the same. So the

contention of the petitioner is to prove that all the manufacturers in the world want to dump their Vitamin-C in India only, which sounds totally wrong and irrational.

- (3) The product under consideration must be broadened to include 2-Keto Gluconic Acid, as the said product is akin to Vitamin – C. It is also within the same ITC classification. M/s ASE are themselves large scale importers of the penultimate product i.e., 2-Keto Gluconic Acid, which is converted into Vitamin-C by a very simple method. There is a direct linkage between this intermediate product and the final product i.e. Vitamin-C in terms of technology, price and the production process. Vitamin-C is manufactured through an elaborate process of more than 16 stages. One of the stages for manufacture of Vitamin-C involves the production of 2-Keto Gluconic Acid. There is a direct correlation between the price of 2-Keto Gluconic Acid and Vitamin-C. It is a well-established principle for the Anti Dumping law that the petitioner who imports cannot seek protection of Anti-dumping

Accordingly, either the petitioner should be debarred from taking protection of Anti-dumping or in the alternative be deemed 'Like Article to' Vitamin-C and Anti-Dumping to be imposed also on the Like Article.

- (4) We submit that no injury is being occasioned to the domestic industry by our imports. The total demand of the alleged product in India is more than 1200 tons, whereas the installed capacity of the complainant who is the only producer is only 430 tones, which itself justify the monopolistic situation. The demand is likely to increase. Even if the complainant produces and sells at 100% of their installed capacity they cannot meet the market requirement or demand and import has to take place to meet the demand of Vitamin-C in India. As the complainant/petitioner is unable to meet the domestic demand, it is unfair for it to restrict imports by seeking imposition of Anti-Dumping Duty.
- (5) Injury to the domestic industry if at all is self-inflicted. The Plant of the complainant is too small and is unviable with no economies of sales. Small installed capacity of the complainant, increases the cost of production of the alleged product and furthermore the complainant has never produced enough even to meet half of the domestic demand. It is the unviable plant size, which is causing injury to the domestic industry.
- (6) M/s Sarabhai have also failed to disclose that for their own captive consumption they have brought imported material on much lower cost, which also results in less offtake from their own consumption resulting in loss of production.

- (7) The main reason for their loss of production and loss of sales is a monopoly situation they were having during earlier times due to restricted imports and bad business policies
- (8) The prices internationally are more or less unchanged in the last three years by all major manufacturers and we wonder why the government has not considered the reason for Sarabhai's tremendous high prices that is 2-1/2 times higher than present international prices by all leading manufacturers
- (9) The petitioners rely upon evidence of a manufacturer from Ireland for the purposes of establishing Normal Value in the EU. At the public hearing, the cooperating exporter from EU, went on record to confirm that there is no producer of Vitamin-C in Ireland. In view of this fact, it is submitted that the entire proceeding concerning the imposition of duty on imports emanating from EU should be void ab-initio.
- (10) The injury to the domestic industry is not due to the dumping but there are some other reasons for injury as process of manufacturing from the petitioner is outdated. The accepted process now starts from 2-Keto Gluconic acid, rather than the sorbitral. This reduces the steps required for the manufacture of Vitamin-C. The cost of production of the petitioner is also higher because of the cost of electricity etc.

In the petitioner's own admission, imports of Vitamin-C into India were highly restricted and the import duty was high. However, in the mid-90s when duties across the board were reduced, and import restrictions were removed, imports started growing. Coupled with the reduction in import duties and dismantling of trade barriers, other manufacturers such as Jayant Vitamins and Jindal Drugs Limited either closed down or shelved their production plans.

- (11) The Authority has erred in determining the normal value of BASF on the basis of cost of production, including administrative, selling, general expenses and interest, depreciation and an element of profit and discarding the sale price in the domestic market.
 - (i) The Designated Authority has not verified the cost data submitted by BASF. The exporter has submitted that
 - ◆ The sale price in Germany is truly representative.
 - ◆ If sale price in Germany was to be ignored for any reason, then sale price to other European Union countries should have been considered and in doing so it must be recognized that prices in Europe are determined by imports into Europe from China.

- (ii) Authorities for the purpose of determining normal value may disregard sales, if they are made at Unit price which are less than per unit cost, i.e. costs of production plus selling, general and administrative expenses (SG&A) and the following two conditions are both satisfied:
- (a) Such sales are made at prices which do not provide for recovery of all cost within a reasonable period of time; and
 - (b) Such sales occur in substantial quantities within an extended period of time.
- ♦ Assuming without admitting that it is correctly computed the sales alleged below cost of production were not at prices which did not provide for recovery of all costs within reasonable period of time. BASF-AG has undertaken significant improvements in expansion of capacity and technology improvements, which will result in significant reduction of costs and increase in profitability and enable the company to recover full cost. This benefit is likely to accrue shortly. This fact which is mandatory has been overlooked by the Designated Authority in arriving at a conclusion to discard sale price in Germany or European Union

C. **EXAMINATION OF ISSUES RAISED:**

The submission made by the exporters, importers, petitioner and other interested parties have been examined and issues raised with reference to the Rules and having a bearing on this case have been considered and dealt with at appropriate places in the notification.

D. **DISCLOSURE OF ESSENTIAL FACTS MADE BY THE AUTHORITY**

The views raised in response to the disclosure statement are discussed in the relevant paras herein below to the extent these are relevant as per rules and have a bearing on the case.

a. **Comments made by Petitioner**

- (i) The petitioner's claim that the duties are imposed on the product as described as "product under consideration" and can not be extended to "Like Article". The issue of like article is relevant in the context of standing and domestic industry and determination of normal value. The product under investigation remains the product dumped in the Indian market in the investigation period. It can not be extended to Like Article.

- (ii) Regarding offer of price undertaking by M/s BASF to the Designated Authority, petitioner has submitted that no price undertaking be accepted by the Designated Authority from the exporter unless they are given a chance to comment on the offer made by the exporter
- (iii) The Designated Authority has recently completed review investigations for the same product for imports from Japan and China. The duties in that case have been recommended on variable basis. The petitioner requests the Designated Authority to recommend variable duties in this case also, so that the interests of the domestic industry are adequately protected and all the imports are at the same level.

b. Comments made by the importers

- (i) The disclosure statement gives only the methodology of arriving at the final findings. No facts or analysis has been indicated in the disclosure statement.
- (ii) With reference to the normal value determinations of the cooperating exporter from EU – M/s BASF, it is not clear whether the sales in the domestic market were below the cost of production for more than a reasonable period of time.

EXAMINATION OF COMMENTS ON DISCLOSURE OF ESSENTIAL FACTS BY THE AUTHORITY

The arguments raised by the interested parties have been examined, considered and, wherever appropriate, dealt in the relevant paras in this notification.

Regarding disclosure of essential facts, Authority has followed the consistent practice of the Directorate as per Rule 16 of Anti-Dumping rules.

E. PRODUCT UNDER CONSIDERATION:

The product considered in the present investigation is Vitamin-C originating in or exported from Russia and European Union (EU). Vitamin-C is classified under the Custom Sub heading 2936.27 of the Custom Tariff Act, 1975. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

F. “DOMESTIC INDUSTRY” STANDING OF THE PETITIONER

The petition has been filed by M/s. Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. having its Registered Office at Wadi Wadi, Baroda-390007. The petitioner is the sole producer of the subject goods in India. The other company M/s. Jayant Vitamin Ltd. that had created capacities for manufacturing Vitamin-C in India has since closed its operations. Therefore, the petitioner accounts for total production of the subject goods in India and fulfils the requisite criteria to represent the domestic industry, as required under the Rules.

As to the standing of the petitioner, an argument has been raised that the petitioner are disqualified to form part of the domestic industry as they are an importer of 2KGA which is the final stage material for Vitamin-C and, therefore, is a Like Article to Vitamin-C. However, the Authority finds that the products 2 KGA and Vitamin-C are not commercially and technically substitutable and the former is only an intermediate product for manufacturing of the latter. Therefore, 2 KGA imported by the petitioner is not considered as a Like article to Vitamin-C. The Authority holds that the imports of 2 KGA by the petitioner does not, therefore, lead to the definition of M/s Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. as importer of Vitamin-C and does not exclude them from the scope of domestic industry under the Rule.

G. LIKE ARTICLES:

In the preliminary determination the Authority held that the Vitamin-C produced and sold by domestic industry and those imported from the subject countries have similar characteristics and should be treated as Like Articles. The Authority also determined that there is no significant difference in the technology adopted by petitioner and by the producers in these countries even though every manufacturer fine-tunes production process according to available facilities and necessities.

Issues raised by some of the interested parties to treat 2KGA as Like Article of Vitamin-C. The Authority has already clarified above in para 5 that 2 KGA is an intermediate product for manufacturing of Vitamin-C, hence can't be treated as Like Article.

In view of the same, the Authority confirms that Vitamin-C produced by domestic industry and those being imported from Subject countries are Like Articles within the meaning of relevant rules.

H. **NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN-EU**

The Authority has examined Normal Value in relation to an article as per the Rules in Section 9A(1)(c) Only M/s. BASF and M/s Merck KGaA filed the response in the case from Germany. The assessment of normal value, export price and dumping margin is as under:-

1 **M/S. BASF, GERMANY**
Normal Value:

- (a) The claims made by the exporters with regard to domestic sales of subject goods during the period of investigation along with cost of production of subject goods in the domestic market, has been verified by the Authority. It is noted that sales are made at prices which do not provide for recovery of all cost within a reasonable period of time and such sales occur in substantial quantities. The exporter has also admitted that the company has sold Vitamin-C in domestic market at a loss i.e. below their cost of production.
- (b) In view of the above, the Authority considers it appropriate to determine normal value on the basis of cost of production, including administrative, selling, general expenses and reasonable profit margin. Since the normal value is based on cost of production including selling, general, administrative expenses and reasonable profit margins, the Authority has not considered any other adjustments.
- (c) Argument raised by M/s BASF and importers regarding normal value assessment on the basis of selling price of Irish Producer, it is clarified that Authority has relied upon this data as prima facie evidence for initiation of the case, accepting the argument that Germany and UK are the part of European Union and having common custom territory, the prices in the whole of the European Union are bound to be the same. Since subsequently some of exporters have responded, Authority has derived its findings on the basis of information supplied by the exporters.
- (d) Regarding significant improvements in expansion of capacity and technology improvements resulting significant cost reduction after period of investigation, the Authority has carried out the investigation in accordance with the Anti-dumping Rules in the instant case and clarifies that the information pertaining only to the Period of Investigation is relevant for the case.

Export Price:

The exporter, M/s BASF, furnished transaction-wise details of export of subject goods to India during the Period of Investigation. After verification, weighted average CIF export price is considered for assessment of export price in case of M/s BASF. The adjustments claimed by the exporter with regard to overseas freight, Inland freight, handling charges and Packing in export sales has been verified by the Authority and considered to be allowed arriving export price at ex-factory level.

DUMPING MARGIN IN RESPECT OF NON-COOPERTIVE EXPORTERS**2. M/S MERCK KgaA, GERMANY****Normal Value**

M/s Merck KgaA has neither furnished the transaction wise details of its domestic sales nor have they furnished the cost of production of Vitamin-C. The exporter neither responded to further queries sought by Designated Authority in this regard nor participated in the public hearing/ submitted any written submissions after preliminary findings

In light of above, the Authority has treated M/s Merck KgaA as Non-co-operative exporter. Therefore, the Authority has determined normal value in respect of M/s Merck KgaA based on the best information available.

Export Price.

The exporter M/s Merck KgaA furnished transaction-wise details of export of subject goods to India during the POI. The weighted average CIF export price is proposed to be considered in assessment of export price. The exporter has not disclosed any adjustments from the CIF export price. The Authority has, therefore, determined the export price on the basis of Rule 6(8), i.e., best information available.

3. OTHER EXPORTERS

The Authority observes that the quantum of exports from European Union are higher than the quantum of exports as reported by M/s. BASF and M/s Merck KgaA together. Therefore, with regard to other exporters from EU, the Authority finds it appropriate to consider the dumping margin as determined in respect of M/s Merck KgaA.

J **NORMAL VALUE , EXPORT PRICE & DUMPING MARGIN
RUSSIA:**

- (a) The Authority provided opportunity to the exporters from Russia to furnish information relevant to the investigations and offer comments, if any, in accordance with the Rule. The Authority also wrote to the Embassy of Russia in India. However, none of the exporters from the subject country has responded to the Authority's request for information.
- (b) The claim made by the petitioner with regard to the determination of normal value has also not been disputed by any interested party (ies). The Authority has, therefore, proceeded on the basis of Rule 6(8), i.e., best information available.
- (c) The normal value was determined at the time of initiation of the investigations on the basis of the constructed cost of production of Vitamin-C in Russia as provided by the petitioner. The Authority has considered the same as the basis for determination of the Normal Value after appropriate adjustments.
- (d) The export price has been determined on the basis of the information compiled by the DGCI&S, Calcutta. The weighted average export price has been adjusted for commission, insurance, inland freight, overseas freight, packing & handling charges as claimed by petitioner.

J The Rules relating to comparison provides as follows:

“While arriving at margin of dumping, the designated authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability.”

Based on the Normal Value and the Export Price, as determined above, the dumping margin in respect of individual exporters and the specific countries, is as under: -

S. No.	Country/Exporter	Dumping Margin %
1.	<u>EU</u> 1) M/s BASF, Germany (subject goods originated from M/s BASF Health & Nutrition, Denmark 2) Other Exporters	49.20 134.73
2.	<u>Russia</u> All Exporters	122.82%

K. INJURY & CAUSAL LINK:

1. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
2. For the examination of the impact of the imports on the domestic industry in India, the Authority considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. in accordance with Annexure II (iv) of the rules supra.
3. The authority has also examined factors other than dumped imports viz. uneconomical plant size, inefficiencies, mismanagement, or any other factors etc. as cited which might be injuring the domestic industry at the same time.

The non-injurious price for the domestic industry has been determined by making appropriate analysis of all relevant factors like usage of raw material, usage of utilities, captive consumption, etc. and the actual expenses during the period of investigations including the investments and capacity utilization. The non-injurious price of domestic industry has been determined by considering the optimum cost of production and considering the reasonable return on the capital employed by the domestic industry.

L. CONCLUSION ON INJURY

1. The Authority concludes that

(a) Production & Capacity utilisation: -

The production of the petitioner company has decreased from 468 961 MT in 1996-97 to 303.713 MT in 1997-98 further decline to 283.842 MT in the period of investigation as against the total demand of about 1200 MT.

The company achieved capacity utilisation of 109% during financial year 1996-97 decreased to 71% during the financial year 1997-98, which further decreased to 66% during the period of investigation on an annualised basis

) Sales Quantity: -

The sales of the petitioner company decline from 413.694 MT during 1996-97 to 269 457 MT during 1997-98 further decline to 234.792 tons during the financial year 1998-99 .

(c) Sales Realisation: -

The average sales realisation of the petitioner company during 1996-97 was Rs.****/Kg marginally increase to Rs***/ Kg during 1997-98 . There was a sharp decline in the sales realisation during the period of investigation and the same was at Rs *****/Kg.. Moreover, the sales realisation of the Petitioner Company during the period was below its cost of production.

(d) Profitability:

During the financial year ending 31st March, 1997, the losses of the company from the Vitamin-C operation was Rs.64 75 lacs increased to Rs 530.13 lacs at financial year ending 31st March 1998. The losses further increased to Rs.573.50 lacs during the year 1998-99 .

(e) Increase in Imports from Subject Countries

Imports from EU has increase from 42.8 MT during 1996-97 to 114.53 MT in 1997-98 marginally decline to 107.581 MT during 1998-99.

Imports from Russia was 30 MT during period of investigation as compare to nil during previous years.

(f) **Decline in Import price from Subject Countries**

Import price from EU was US\$ 3.66/Kg CIF during 1996-97 , decline to US\$ 2.66/Kg CIF during 1997-98 marginally increase to US\$ 2.78/Kg CIF during 1998-99. Imports price from Russia was US\$ 2.61/Kg CIF during period of investigation .Authority has observed that because of such a low priced imports domestic industry was not in a position to recover the DPCO price.

(f) **Closing Stock**

Closing stock of the petitioner was 1.862MT during 1996-97 increased to 4.345 MT during 1997-98 come down to 3.95 MT during period of investigation

(g) **Employment**

The petitioner has reduced its staff strength from 482 during 1996-97 to 311 in period of investigation to reduce the losses to some extent.

- 2 The Authority, therefore, notes from the above that the imports from the subject countries have been at a price below the selling prices of the domestic industry Further, the imports into India have been at a price lower than the non-injurious price for the domestic industry. As a consequence thereof the petitioner was forced to sell its product at a price significantly below its non-injurious price resulting in financial losses to the petitioner. The petitioner was also prevented from increasing the level of capacity utilisation.

These parameters collectively and cumulatively indicate that the petitioner has suffered material injury due to the dumped imports

M. **INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES**

- 1 The purpose of anti dumping duties, in general, is to eliminate dumping which is causing injury to the petitioner companies and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.
- 2 It is recognised that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures, particularly if the levy of the anti dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the

injury to the petitioner company. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the petitioner company and help maintain availability of wider choice to the consumers of Vitamin-C. Imposition of anti dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

3. To ascertain the extent of anti-dumping duty necessary to remove the injury to the petitioner company, the Authority has relied upon non - injurious selling price of Vitamin-C in India for the petitioner company, by considering the optimum cost of production at optimum level of capacity utilisation for the petitioner company

N. **CONCLUSIONS:**

The Authority, after considering the foregoing, concludes that:

- (a) Vitamin-C originating in or exported from the subject countries has been exported to India below its normal value, thereby resulting in dumping.
- (b) The domestic industry has suffered material injury
- (c) The injury has been caused to the domestic industry by dumping of the subject goods originating in or exported from Russia and EU.

O **FINAL FINDINGS**

The Authority, after considering the foregoing, concludes that:

- (a) Therefore, the Authority recommends imposition of definite anti-dumping duty on all imports of Vitamin-C falling under chapter 29 (Custom Sub-heading 2936.2700) originating in or exported from Russia and EU.
- (b) The landed value of imports for the purpose shall be assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9 and 9 A of the Customs Tariff Act, 1975.
- (c) It was considered to recommend the amount of Anti-Dumping Duty equal to the dumping margin or less which, if levied, would remove the injury to the domestic industry Landed value of the imports for individual exporters, for the purposes, were compared with the non-injurious selling price of the domestic industry, determined for the period of investigation Wherever the difference was less than the dumping margin, a duty lower than the dumping margin is recommended.

- (d) Accordingly, anti-dumping duties may be imposed, on all imports of Vitamin-C originating in or exported from the subject countries. The anti-dumping duty shall be the difference between the amounts mentioned in column 3 below and the landed value of imports in US \$/Kg.

1	2	3
SI.No.	Name of the Company	Amount (US \$ per Kg)
1.	<u>EU</u> 1) M/s BASF, Germany (M/s BASF, Germany (subject goods originated from M/s BASF Health & Neutrition, Denmark) 2) Other Exporters	 11.29 12.67
2.	<u>RUSSIA</u> All Exporters	12.67

- (e) Subject to the above, the authority confirms the Preliminary Findings dated 17th January, 2000
- (f) An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

RATHI VINAY JHA. Designated Authority